परती भूमि का उपयोग

@1274. **श्री वीरेन जे० शाह :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में किये गये आकलन के अनुसार देश में 158 मिलियन हेक्टेयर परती भूमि है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस अप्रयुक्त भूमि में वृक्षारोपण कर इसे वन के रूप में विकसित करने के लिये कोई योजना तैयार की है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि परती भूमि को सरकारी स्तर पर विकसित करने के लिये किये गये उपायों से कोई विशेष सफलता दिखाई नहीं दी है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) क्या सरकार अब इस भूमि के विकास के लिये आम जनता को भागीदार बना कर कोई योजना तैयार करने का विचार रखती है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं । 1989-90 में पुरानी परती भूमि तथा नई परती भूमि लगभग 26.34 मिलियन हैक्टेयर होने का अनुमान है।

(ख) राष्ट्रीय वनरोपण तथा परिस्थितिकी विकास बोर्ड, जो पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अधीन है, वनरोपण/वृक्षारोपण के माध्यम से निम्नीकृत वनों को पुनः उत्पादक उपयोग में लाने के लिए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न केन्द्रीय/राज्य योजनाओं के अन्तर्गत भी वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं, जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं---(1) राज्य योजनाएं (2) विदेशी सहायता प्राप्त वन परियोजनाएं (3) निम्नीकृत वनों का सुधार (4) पट्टीदार बागान (5) फार्म वानिकी तथा उत्पादन वानिकी, एवं (6) जलावन लकड़ी तथा चारा उत्पाद आदि ।

(ग) और (घ) राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों की वजह से पुरानी परती भूमि तथा नई परती भूमि के अन्तर्गत आने वाला क्षेत्र कम हो गया है और इसमें लगातार गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है अर्थात् 1950-51 के लगभग 28.12 मिलियन हैक्टेयर से घटकर यह 1989-90 में 26.34 मिलियन हैक्टेयर रह गया है ।

(ङ) परती भूमि तथा निम्नीकृत क्षेत्रों संबंधी भूमि आधारित सभी विकास कार्यक्रमों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने आठवीं योजना में जन सहभागिता पर बल दिया है। परती भूमि सहित निम्नीकृत्त भूमि की उत्पादकता में सुधार करना उन क्षेत्रों में से एक है जिन पर बल दिया जा रहा है एवं साथ ही निम्नलिखित चालू योजनाओं में वृक्षारोपण, वनस्पति प्रसार तथा बायोमास उत्पादन घटक सम्मिलित हैं :

(1) नदी घाटी परियोजनाओं के जल-ग्रहण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना;

(2) बाढ़ प्रवण नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में स्वीकृत पनधारा प्रबंध की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना;

(3) वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना;

(4) उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में क्षारीय मृदा सुधार संबंधी केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना;

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 518, 29 अप्रैल, 1993 से स्थानान्तरित ।

(5) उत्तर प्रदेश में बीहड़ क्षेत्र सुधार संबंधी यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त परियोजनाएं;

(6) मरूस्थल विकास कार्यक्रम; और

(7) राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत मृदा संरक्षण एवं पनधारा प्रबंध कार्यक्रम ।

Conference of Scientists on Various Uses of Neem

@@1275. SHRI SOM PAL :
DR. NAUNIHAL SINGH :

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether a conference of scientists on various uses of neem tree was recently held at Bangalore;

(b) if so, the participants therein and the main conclusions of their deliberations;

(c) what are the uses of neem identified therein;

(d) whether Government are contemplating to formulate any action plan based on the recommendations/suggestions made by this meet; and

(e) if so, what are the details thereof, and the manner in which Government propose to implement these recommendations ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI S. KRISHNA KUMAR) : (a) Yes, Sir

(b) The World Neem Conference was attended by about 450 delegates including 80 foreign delegates from 30 different countries. Indian delegates represented various govt. and non-govt. organisations, universities and the industries.

The Conference confirmed the value and the potential of neem and similar plants in sustainable agriculture, specially pest control, public and veterinary health and family planning.

(c) The Conference recognised the role of neem as pesticide including mosquito control; as fertiliser and in medicine for public and animal health. In addition, the use of neem in soap and oil industry was also identified.

(d) and (e) High priority to promote use of neem as one of the environmentally safe methods for pest control.

The Registration Committee established by the Government under the Insecticide Registration Act of 1968 has simplified the procedure to encourage commercialisation of the neem products for pest control for the benefit of the farmers.

Cultivation of Mushrooms

1276. SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the District Rural Development Authority of Rajasthan has launched a scheme to cultivate the highly nutritious Oyster mushrooms;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether it is a fact that the scheme has vast potential of providing

@@Previously Unstarred Question 522, transferred from 29th April, 1993.